नागरिक समीक्षा

माननीय म्यायमूर्ति हरबंस सिंह के समक्ष

शिव कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

मूल चाइद, आदि,-प्रतिवादी

सिविल रिवीज़न क्रमांक 555, 1971

4 अगस्त 1971.

हिंदू कानून-संयुक्त हिंदू परिवार के पास संपत्ति होना-परिवार का कर्ता कानूनी आवश्यकता के बिना ऐसी संपत्ति को अलग करने की कोशिश करना-अन्य सह। भागीदार-क्या इस तरह के अलगाव को रोका जा सकता है, इन-जंक्शन के लिए एक सूट लाकर।

यह निर्णय लिया गया कि यदि संयुक्त हिंदू परिवार के करता का कोई कार्य उस कानून के अनुसार अवैध है जिसके द्वारा वह शासित होता है, और यदि सहदायिकों को इस विचारित कृत्य के बारे में पता चलता है, तो उन्हें उसे ऐसा करने से रोकने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसा करना और इस प्रकार एक निर्दोष विदेशी व्यक्ति को आगे की मुकदमेबाजी से बचाना। यह संभवत: कानून नहीं हो सकता कि उन्हें लेन-देन पूरा होने तक इंतजार करना होगा और फिर संपत्ति वापस पाने के लिए कदम उठाना होगा। इसलिए जब संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है और कर्ता द्वारा प्रस्तावित अलगाव परिवार के लाभ के लिए या कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं है, तो कोई भी सहदायिक निषेधाज्ञा का मुकदमा लाकर ऐसे अवैध कार्य को रोक सकता है। (पैरा 8 और 12.)

1919 के अधिनियम IX की धारा 44 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत श्री टी. पी. गर्ग, वरिष्ठ उप न्यायाधीश (के साथ) के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियाँ), नारनौल, दिनांक 16 अप्रैल, 1971, श्री एस.आर. बंसल, उप न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, नारनौल की दिनांक 21 दिसंबर, 1970 को पलटते हुए, आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रतिवादी शिव कुमार वादी के आवेदन को खारिज कर दिया। धारा 151 सी.पी.सी., और पक्षों को 20 मई, 1971 को आगे की कार्यवाही के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देना।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ए.एस. आनंद और मदन लाल।

प्रतिवादियों की ओर से एच. एल. सरीन, वकील के. आर. चौधरी और एम. एल. सरीन।

निर्णय

हरबंस सिंह, सी.जे.

-यह संशोधन एक दिलचस्प बात उठाता है, शिव कुमार, जो मेरे समक्ष याचिकाकर्ता हैं, ने अपने पिता और अपने दो भाइयों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्हें विवाद में संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है, जैसा कि आरोप लगाया गया था। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होना। वाद में आरोप थे कि उनके पिता मूलचंद अपने दो अन्य बेटों, दीना नाथ और सत्य पाल की मिलीभगत से, बिना किसी वैध कानूनी आवश्यकता या परिवार और संपत्ति के किसी भी लाभ के बिना विवाद में संपत्ति को हस्तांतरित कर रहे थे और वादी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए अलगाव किया जा रहा था।

(2) संपत्ति की पैतृक प्रकृति को पिता ने नकार दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि संपत्ति उनकी स्व-अर्जित थी। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस आशय की कोई बात नहीं कही है कि वह किसी कानूनी आवश्यकता के लिए संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं।

(3) वादी द्वारा उसके पिता और उसके भाइयों द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को हस्तांतरित करने से एक अस्थायी निषेधाज्ञा का भी दावा किया गया था। यह ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन निचली अपीलीय अदालत ने मामले की प्रथम दृष्टया योग्यता पर विचार करने के अलावा, चाहे संपत्ति पैतृक थी या नहीं, यह देखा कि हिंदू कानून के अनुसार, जैसा कि पंजाब में प्रथा द्वारा संशोधित किया गया था, ए पुत्र अपने पिता के जीवनकाल के दौरान संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का हकदार नहीं है और परिणामस्वरूप, एक पुत्र के पास अपने पिता को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को अलग करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और उसके पास एकमात्र उपाय उपलब्ध है वह यह है कि, अलगाव के बाद, वह इस आधार पर अलगाव को चुनौती देने वाला मुकदमा ला सकता है कि कानूनी आवश्यकता नहीं होने के कारण यह परिवार पर बाध्यकारी नहीं है। में उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने निषेधाज्ञा आदेश को रद्द कर दिया और वादी ने यह पुनरीक्षण दायर किया है।

(4) जहां तक संपत्ति की पैतृक प्रकृति का प्रश्न है, यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जिस पर मुकदमे के इस प्रारंभिक चरण में विचार नहीं किया जा सकता है और मैं इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।

(5) निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या, यदि संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, तो एक पुत्र, एक सहदायिक होने के नाते, परिवार के प्रबंधक या कर्ता को, जो उसका पिता भी हो सकता है, को रोकने का हकदार है। बिना किसी कानूनी आवश्यकता के संपत्ति को अलग करना और इस प्रकार परिवार और विशेष रूप से वादी-बेटे को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के आनंद से वंचित करना। मामले की सुनवाई कल हुई थी और वकील को इस मामले को देखने में सक्षम बनाने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था।

(6) जहां तक कर्ता के अधिकार का सवाल है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को केवल कानूनी आवश्यकता और संपत्ति के लाभ के लिए अलग कर सकता है। यदि कर्ता पिता होता है, तो, जैसा कि मुल्ला के हिंदू कानून के अनुच्छेद 256, पृष्ठ 290 में देखा गया है, उसके पास "अपने बेटों, पोते-पोतियों के हित सहित, पैतृक संपत्ति, चाहे वह चल या अचल हो, बेचने या गिरवी रखने की शक्ति है।" और उसमें परपोते,

अपने स्वयं के ऋण के भुगतान के लिए, बशर्ते कि ऋण एक पूर्व ऋण था और अनैतिक या अवैध उद्देश्यों के लिए नहीं लिया गया था। लेखक फिर कहता है कि "उपरोक्त के अलावा, एक पिता के पास इससे बड़ा कोई नहीं है किसी भी अन्य प्रबंधक की तुलना में सहदायिक संपत्ति पर अधिकार, यानी, वह कानूनी आवश्यकता के अलावा या परिवार के लाभ के लिए सहदायिक संपत्ति को अलग नहीं कर सकता है।"

(7) ऐसा होने पर, निर्धारण का एकमात्र बिंदु यह है कि, यदि कर्ता कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि संपत्ति को अलग करने की कोशिश करता है, तो क्या उसे अन्य सहदायिकों द्वारा रोका जा सकता है या अन्य सहदायिकों को देखना होगा और कर्ता को संपत्ति से अलग होने देना होगा बिक्री, बंधक या अन्यथा द्वारा संपत्ति और उसके बाद ऐसे स्थानांतरण को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर करना,

(8) किसी भी कानून के अलावा, सामान्य ज्ञान को यह निर्देश देना चाहिए कि यदि कर्ता का कोई कार्य अवैध है, तो उस कानून के अनुसार जिसके द्वारा वह शासित होता है, और यदि सहदायिकों को विचार किए गए कार्य के बारे में पता चलता है, तो उन्हें एक स्थिति में होना चाहिए उसे ऐसा करने से रोकने के लिए और इस प्रकार एक निर्दोष विदेशी व्यक्ति को आगे की मुकदमेबाजी से बचाया जा सकता है और यह संभवतः कानून नहीं हो सकता है कि उन्हें लेनदेन पूरा होने तक इंतजार करना होगा और फिर संपत्ति वापस पाने के लिए कदम उठाना होगा।

(9) एन.आर.राघवाचार्य ने हिंदू कानून पर अपने ग्रंथ, छठे संस्करण में, पृष्ठ 298 पर पैराग्राफ 269 में, विशेष रूप से इस विषय से संबंधित है। शीर्षक है "अनुचित कार्यों को रोकने का अधिकार" और यह इस प्रकार चलता है: "एक सहदायिक, जो कोई ऐसा कार्य करता है जो या तो अवैध या अनुचित है और संयुक्त हितों या आनंद के लिए प्रतिकूल है, उसे अन्य सहदायिकों के कहने पर निषेधाज्ञा द्वारा ऐसे कार्य से रोका जा सकता है। बीच में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा संयुक्त परिवार की संपत्ति के संदर्भ में एक सहदायिक के सदस्यों के मामले में, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बर्बादी के कृत्यों, पारिवारिक संपत्ति के नाजायज उपयोग या बेदखली के कृत्यों तक सीमित है... ”

(10) अनंत रामराव बनाम बलवंत (एलएलआर। 19 बम. 269) में, इसे इस प्रकार देखा गया: "संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच संयुक्त संपत्ति के संबंध में विवाद में, निषेधाज्ञा द्वारा राहत देने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बर्बादी के कृत्यों, पारिवारिक संपत्ति के नाजायज उपयोग, या निष्कासन के कृत्यों तक ही सीमित होना चाहिए। " उस मामले में, सवाल यह था कि क्या वादी घर के उस हिस्से का आनंद ले रहा था जिसके उपयोग से उसे बेदखल किया जा रहा था, और उस मामले के लिए मामले को उचित निष्कर्ष देने के लिए जिला न्यायालय में वापस भेज दिया गया था। जो भी हो, तथ्य यह है कि एक न्यायालय निषेधाज्ञा दे सकता है जहां सहदायिकों में से एक अपने गलत कार्य से संपत्ति को बर्बाद करने की कोशिश करता है, या उसका नाजायज उपयोग करता है या इस तरह से कार्य करता है जो बेदखल करने के समान है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई सहदायिक बिना किसी कानूनी आवश्यकता के संपत्ति बेचता है और जिसके लिए वह कानून के तहत अधिकृत नहीं है, तो वह निश्चित रूप से अन्य सहदायिकों को बेदखल कर रहा है।

(11) राघवाचारियों के हिंदू कानून के पृष्ठ 351 पर, अनुच्छेद 306 में, एक पिता द्वारा अलगाव को विशेष रूप से इस प्रकार निपटाया गया है: - "एक पिता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण न तो पारिवारिक आवश्यकता के लिए और न ही अपने पूर्ववर्ती ऋण के लिए होता है, एक सहदायिक द्वारा अलगाव के समान ही प्रभाव, जो न तो प्रबंधक है और न ही संयुक्त परिवार का पिता है।"

(12) उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे इसे एक उचित मामला मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, यानी, जहां संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है (यह मानते हुए कि यह वादी द्वारा साबित किया गया है) और प्रस्तावित ग्रहणाधिकार किसी के लाभ के लिए नहीं है परिवार या कानूनी आवश्यकता के लिए सहदायिकों में से कोई भी ऐसा लाकर ऐसे अवैध कार्य को रोक सकता है निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा।

(13) उपरोक्त कारणों से, मुझे लगता है कि निचली अपीलीय अदालत का निर्णय और आदेश, कानून की पूरी तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़े, जिससे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता हुई। इसलिए, मैं इस संशोधन को लागतों के साथ स्वीकार करता हूं, शीर्ष अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करता हूं और ट्रायल कोर्ट की सूचना को बहाल करता हूं, जो निचली अदालत को भेजी जाएगी।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा